

अजीबो-गरीब तर्क दिए जा रहे हैं, वेणुगोपाल को मु.मंत्री बनाने के लिए

एक तर्क है कि आगामी यूपी चुनाव व 2029 के आम चुनाव की दृष्टि से पार्टी को हिन्दी भाषी संगठन महासचिव चाहिए, अतः वेणुगोपाल को संगठन महासचिव से हटाकर मु.मंत्री बनाकर, केरल भेज देना चाहिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। केरल में भारी मतों से जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चयन करने को लेकर भारी उलझन में है। हर नजरिए से के.सी. वेणुगोपाल इस रस में आगे हैं, क्योंकि उन्होंने टिकटों का वितरण किया है और इस कारण कई विधायकों की कथित वफादारी उनके पक्ष में है। लेकिन ज़मीन पर हकीकत कुछ और ही है।

केरल घर में कांग्रेस के लोग और यहाँ तक कि कांग्रेस के समर्थक और मतदाता के.सी. वेणुगोपाल के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पोस्टर और पुतले जला

- अब, पुराना तर्क है कि विधायकों का बहुमत वेणुगोपाल के पक्ष में है, नहीं दोहराया जा रहा, क्योंकि सभी जानते हैं कि वेणुगोपाल ने केरल में टिकट बाँटे हैं। अतः विधायकों की सतही वफादारी वेणुगोपाल के पक्ष में तो होगी ही।
- विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन की टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं थी। अतः सतही तौर पर, सतीशन के पक्ष में बोलने वाले बहुत कम विधायक हैं। पर, सतीशन के सीपीएम सरकार के खिलाफ विधानसभा में पाँच साल तक चलाए गए संघर्षपूर्ण अभियान के लिए विधायकों में बहुत आदर है। अतः अगर सतीशन को मु.मंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस विधायक दल बिखर सकता है।
- क्या इस बिखराव का जोखिम उठाकर भी कांग्रेस वेणुगोपाल पर दांव लगाएगी?
- सतीशन, रमेश चैन्सिथाला, वेणुगोपाल आदि को रविवार को दिल्ली बुलाया गया है तथा पार्टी के समक्ष दुविधा पर मंथन कर, समाधान निकालने की एक बार फिर चेष्टा होगी।

रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ खुला विरोध जता रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने छात्राओं की माँग तुरंत पूरी की

जयपुर/सीकर, 8 मई। 'बेटी पढ़े, बेटी बड़े' की भावना को साकार करते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संवेदनशील कार्यशैली का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। जिला सीकर के ब्लॉक खंडेला स्थित जाजोद गांव की बालिकाओं ने रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री से जो माँग रखी, वह आज सुबह होते-होते पूरी हो चुकी थी। गुरुवार को रात्रि चौपाल के दौरान जाजोद गांव की कई छात्राएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलीं और अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में विज्ञान

- रात्रि चौपाल में छात्राओं ने विज्ञान संकाय की माँग की, मुख्यमंत्री ने सुबह संकाय खोलने की घोषणा कर दी।

संकाय की सुविधा नहीं है, जिसके कारण उन्हें या तो मजबूरी में अन्य विषयों से पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर विज्ञान पढ़ने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता है। बालिकाओं की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें आश्वासन दिया कि उनके स्कूल में विज्ञान संकाय अवश्य खोला जाएगा। रात को ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। शुरुवार सुबह जब बालिकाएं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमारे 300 से अधिक कार्यकर्ता को पीछा करके मारा गया था'

"उस समय शुभेन्दु अधिकारी ने पार्टी को बाँधे रखा था और तुरंत भाग कर वहाँ पहुँचते थे, जहाँ जब भी पार्टी संकट में होती थी"

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। सभी अनिश्चितताओं को दरकिनार करते हुए शुभेन्दु अधिकारी को नव निर्वाचित भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। इसी बीच, कोलकाता में एक क्रांति चल रही है। न्यू टाउन क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर से दूर, नए मुख्यमंत्री की घोषणा की गई, कोलकाता की ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग, जो कभी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इंपीरियल सेक्रेटरीयट हुआ करती थी, आज अपने मूल लाल रंग के ऊपर चमक रही है। वर्षों की उपेक्षा और खस्ता हालत के बाद, जब राइटर्स बिल्डिंग वीरान हो गई थी और राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ से शिफ्ट हो गया था, डलहौजी स्क्वायर आज रात एक रहस्यमय आभा बिखेर रहा है, जिसका प्रतिबिंब "लाल दीधी" (मानव निर्मित विशाल तालाब) में नजर आ रहा है।

- इस माहौल में शुभेन्दु के अलावा किसी और को मु.मंत्री पद का उम्मीदवार बनाना, पार्टी में भारी निराशा व विरोध पैदा करता।
- इस अवसर पर बड़े सोच समझकर, कई पुरानी परम्पराएं पुनः जीवित की गईं। शुभेन्दु अधिकारी के मु.मंत्री बनने की घोषणा ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से की, जो कभी ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के साम्राज्य का शाही सचिवालय था। बीच में शासन न्यू टाउन एरिया के कन्वेंशन सेंटर से चलाया जाने लगा था, तथा राइटर्स बिल्डिंग वीरान सी पड़ी रहती थी।
- आज इस अवसर पर, पुराने स्मरणीय स्थल, जैसे, डलहौजी स्क्वायर, पश्चिम बंगाल के विधानसभा भवन को भगवा रोशनी कर जगमगाया गया था, जो कल तक लाल रंग में डूबा रहता था।

मानो राइटर्स बिल्डिंग से प्रतिस्पर्धा करते हुए, पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन, जो कभी इंपीरियल लेजिस्लेचर हुआ करता था, भी केसरिया रंग में नहा रहा है।

और नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने से पहले ही, राज्य-स्वामित्व वाले आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर की मौत की जाँच के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टीवीके के सभी 107 विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी दी थी

क्योंकि डीएमके और अनाद्रमुक के गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश करने की संभावना उभरी थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। विजय की तमिलनाडु वेनी कजगम (टीवीके) ने चेतावनी दी है कि अगर दो द्रविड़िय पार्टियों में से कोई भी, एम.के. स्टालिन की द्रमुक (टीएमके) या ई. पलानीस्वामी की अनाद्रमुक तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश करता है, तो पार्टी के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे।

यह निर्णय द्रमुक और अनाद्रमुक शिविरों में हुई दो महत्वपूर्ण बैठकों के तुरंत बाद आया। टीवीके को संदेह है कि दोनों पार्टियाँ राज्य में सरकार बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं, जिससे वह पार्टी बाहर हो जाए, जिससे जनमत में सबसे अधिक वोट जाए।

टीवीके, जिसने 107 सीटें जीतीं, का कहना है कि अकेली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना

- दोनों द्रविड़ दलों के साथ आने की संभावना इसलिए उभरी थी, क्योंकि डीएमके के युवा नेताओ को भय है कि अगर विजय मुख्यमंत्री बन गए तो वे दूसरे एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) साबित होंगे, जिन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने जीते जी डीएमके को सत्ता के पास भी नहीं फटकने दिया।

चाहिए।

लेकिन आज सुबह, राज्यपाल आर.वी. अरलेकर ने विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने की अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि उनके पास आवश्यक संख्या नहीं है। उन्होंने वह योजना भी स्वीकार नहीं की, जो विजय ने बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए प्रस्तुत की थी। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक - दो दिनों में दूसरी, राज्यपाल ने इस शर्त पर समाप्त की कि अभिनेता-राजनेता को 118 विधायकों से समर्थन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

राज भवन की एक सूचना में कहा गया कि राज्यपाल ने "तमिलनाडु विधान सभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत समर्थन स्थापित नहीं होने" की बात समझाई। टीवीके को बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए 10 और सीटों की जरूरत है और उसके पास पहले से ही कांग्रेस का समर्थन है, जिसके पाँच विधायक हैं। शेष सीटों के लिए लेफ्ट और कुछ छोटी पार्टियों के साथ बातचीत जारी है। सूत्रों ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

जयपुर, 8 मई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में एक्टिंग सीजेएसपी शर्मा सुबह 8.30 बजे करेंगे। प्राधिकरण के

- मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा शुभारंभ करेंगे।

सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्रि ने बताया कि हाईकोर्ट सहित, सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत के तहत कुल 479 बैचों का गठन किया गया है, जिनमें कुल 7.77 लाख से अधिक मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

विजय आज शपथ लेंगे तमिलनाडु के मु.मंत्री पद की

अन्ततोगत्वा तमिलनाडु के राज्यपाल को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी ज़िद बेबुनियाद थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई के समर्थन के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए, टीवीके प्रमुख विजय ने आज शाम तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अरलेकर ने लंबे समय तक चली अटकलों, अफवाहों और अनिश्चितता को समाप्त करते हुए उन्हें कल सुबह 11 बजे शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस घटना कुछ ही घंटे पहले जब लेफ्ट पार्टियों ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। विजय की पार्टी, जिसने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतीं, पहले सीपीआई, सीपीएम और वीसीके, जो सभी द्रमुक की सहयोगी हैं, से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांग

- शुरुवार को राज्यपाल के साथ तीसरी मुलाकात में विजय ने कांग्रेस के अलावा वीसीके, दोनों वामपंथी दलों (सीपीआई और सीपीआईएम) और आईएमएल के समर्थन का प्रमाण पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण देना ही पड़ा।

- तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के 107 विधायक हैं, उसे कांग्रेस के 5, वीसीके के दो, सीपीआई के दो, सीपीआईएम के दो व आईएमएल के दो विधायकों का भी समर्थन मिल गया है, इस प्रकार विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन है।

- विजय को सबसे बड़ी सफलता तब मिली, जब वीसीके ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीसीके प्रमुख को मनाया था।

चुकी थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समर्थन भी प्राप्त हुआ है, जिससे टीवीके को आईएमएल को का गठबंधन का बहुमत 120 सीटों तक

पहुँच गया। सप्ताह में राज्यपाल के साथ विजय की यह तीसरी मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल के पास अब विजय के दावे को खारिज करने का कोई बहाना नहीं बचा।

टीवीके के एक सूत्र ने बताया कि बैठक के दौरान विजय ने सरकार बनाने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। संख्या बल अब विजय के पक्ष में है। टीवीके के पास 234-सदस्यीय विधानसभा में 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने पाँच विधायकों के साथ समर्थन दिया है। सीपीआई और सीपीएम, जिनके दो-दो विधायक हैं, ने भी आंतरिक बैठकों के बाद टीवीके का समर्थन किया। विद्युथलई चिन्थाइल काच्ची (वीसीके), जिसके पास दो विधायक हैं, ने भी विजय का समर्थन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टीवीके को कांग्रेस का समर्थन अवसरवादी राजनीति - मणिशंकर अय्यर

नई दिल्ली, 08 मई। पूर्व केन्द्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में तमिलनाडु वेनी कजगम (टीवीके) के साथ गठबंधन करने के कांग्रेस के फैसले को शुरुवार को अवसरवादी

- पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने इसे अनैतिक कृत्य बताया।

कारार दिया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा की राजनीति तथा महात्मा गांधी की 1925 के उस कथन का अक्षम्य उल्लंघन है कि स्वराज का मतलब नैतिकता पर आधारित सरकार होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहा कि कांग्रेस ने टीवीके के विजय को अपने साथ जोड़कर अनैतिक कृत्य किया है। मणिशंकर ने कहा, द्रमुक के साथ चुनाव लड़ने के तुरंत बाद उस टीवीके के साथ गठजोड़ करने का फैसला बहुत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 मई। द्रमुक नेता कनिमोई ने शुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर, द्रमुक सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने की माँग की। उनकी पार्टी अब कांग्रेस से अलग हो चुकी राजनीतिक गलियारों में इसे केवल संसदीय व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि कहीं अधिक गंभीर राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसका अर्थ 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में गहरी राजनीतिक और वैचारिक दूरी के सार्वजनिक संकेत के रूप में लगाया जा

रहा है। यह घटना तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरणों में तेजी हुए से बदलाव के बीच आई है, जहाँ अभिनेता-राजनेता विजय के उभरने के साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एकता के भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता देखी जा रही है। कई वर्षों तक द्रमुक और कांग्रेस मिलकर तमिलनाडु में प्रमुख पार्टी भाजपा धुरी का प्रतिनिधित्व करती रही है। उनका गठजोड़ अक्सर धर्मनिरपेक्ष विपक्षी राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हालाँकि, संसद में अलग बैठने की माँग अब प्रतीकात्मक रूप से उस सहजता में कमी को दर्शाती है।

- कनिमोई ने जिस तरह से यह फैसला लिया है, वह पार्टी में उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत है। डीएमके में यही व्यवस्था रही है कि स्टालिन राज्य संभालेंगे और कनिमोई दिल्ली में पार्टी को नेतृत्व देंगे।

- अब चूंकि स्टालिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, इसलिए कनिमोई का प्रभाव बढ़ रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम द्रमुक की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण तलाश रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राज्य में नए क्षेत्रीय दलों के उभरने और मतदाताओं की बदलती आकांक्षाओं के

बीच द्रमुक पर अपनी दीर्घकालिक निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। संसद में अलग बैठने की माँग को इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि द्रमुक संसद में अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करना चाहती है, विशेष रूप से संघवाद, भाषा राजनीति और प्रस्तावित सीमा-निर्धारण प्रक्रिया

जैसे मुद्दों पर, जहाँ पार्टी ने दक्षिणी राज्यों पर केन्द्रित आक्रामक रुख अपनाया है। दिलचस्प बात यह है कि इस कदम से पहले ही आम चुनावों के बाद कई क्षेत्रीय मतभेदों का सामना कर चुके इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर भी विपक्ष के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है।

राजनीतिक मजबूरियाँ अंततः राष्ट्रीय विपक्षी एकता को प्रभावित कर सकती हैं। द्रमुक के भीतर भी यह घटना कनिमोई द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक संदेशों को आकार देने में निभाई जा रही बढ़ती संसदीय भूमिका को उजागर करती है। जहाँ मुख्यमंत्री एम के स्टालिन तमिलनाडु में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कनिमोई दिल्ली में पार्टी की प्रमुख राजनीतिक आवाजों में से एक के रूप में उभर रही हैं। सतही स्तर पर यह केवल बैठने की एक साधारण पुनर्व्यवस्था दिखाई दे सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है।

- लोग इसमें ममता का राजनीतिक संदेश देख रहे हैं।

भी उनकी पहचान मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज है। इसे लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ममता बनर्जी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मुख्यमंत्री शब्द बने रहना केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)